



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4172]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 24, 2018/कार्तिक 2, 1940

No. 4172]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2018/KARTIKA 2, 1940

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2018

**का.आ. 5377(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् हिंदु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई (जिसे इस आदेश में "आवेदक" कहा गया है) से संबंधित किसी व्यक्ति की बाबत नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अधीन किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए या धारा 6 के अधीन देशीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए प्रयोक्तव्य शक्तियों का निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा—

(क) निम्न जिलों के संबंध में कलकटर, जिसकी अधिकारिता के भीतर आवेदक साधारण रूप से निवासी है—

- (i) छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर;
- (ii) गुजरात राज्य में अहमदाबाद, गांधीनगर तथा कच्छ;
- (iii) मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल तथा इंदौर;
- (iv) महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, मुम्बई, पुणे तथा ठाणे;
- (v) राजस्थान राज्य में जोधपुर, जैसलमेर तथा जयपुर;
- (vi) उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ; और

(vii) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पश्चिमी दिल्ली तथा दक्षिणी दिल्ली; और

(ख) खंड (क) के अधीन नहीं आने वाले जिलों के संबंध में, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में, यथास्थिति, गृह विभाग का सचिव, जिसकी अधिकारिता के भीतर आवेदक साधारण रूप से निवासी है,

नागरिकता नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रयोग किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) उक्त नियमों के अधीन आवेदक द्वारा भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण या भारत के नागरिक के रूप में देशीयकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन आनलाइन किया जाएगा ;
- (ख) आवेदक का सत्यापन, यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर साथ-साथ किया जाएगा तथा आवेदन एवं उससे संबंधित रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को एक साथ आनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी;
- (ग) आवेदक की उपयुक्तता को अभिनिश्चित करने के लिए, यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव जैसा आवश्यक समझे वैसी जांच कराएगा तथा उस प्रयोजन के लिए उस आवेदन को आनलाइन ऐसे अभिकरणों को सत्यापन और टिप्पणियों के लिए भेजेगा जो ऐसी जांच पूर्ण करने के लिए अपेक्षित हों और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र और जिला द्वारा कठोर अनुपालन किया जाएगा;
- (घ) खंड (ग) में उल्लिखित अभिकरणों की टिप्पणियों को ऐसे अभिकरणों द्वारा आनलाइन अपलोड किया जाना है तथा इन्हें, यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव और केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराया जाना है;
- (ङ) यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव आवेदक/आवेदिका की उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर आवेदक/आवेदिका को रजिस्ट्रीकरण अथवा देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान करेगा और उक्त नियमों में यथा विहित प्ररूप में आनलाइन पोर्टल से सम्यक् रूप से मुद्रित तथा, यथास्थिति, कलक्टर या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा;
- (च) उक्त नियमों के अनुसार, कलक्टर और सचिव द्वारा एक आनलाइन/ डिजिटल के साथ-साथ भौतिक रजिस्टर भी रखा जाएगा जिसमें भारत के नागरिक के रूप में इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत अथवा देशीयकृत व्यक्तियों का ब्यौरा होगा तथा उस रजिस्टर की एक प्रति ऐसे रजिस्ट्रीकरण अथवा देशीयकरण के सात दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।
2. यह आदेश दिनांक 22 दिसंबर, 2018 से प्रवृत्त होगा और अगले आदेश तक वैध रहेगा।

[फा. सं. 26030/266/2014-आईसी-II (एस.ओ.)]

अनिल मलिक, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### ORDER

New Delhi; the 23rd October, 2018

**S.O. 5377(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby directs that powers exercisable by it, for registration as a citizen of India under section 5 or for grant of certificate of naturalisation under section 6 of the Citizenship Act, 1955, in respect of any person belonging to minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians (herein this Order referred to as "the applicant"), residing in the States of Chhattisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh and Union Territory of Delhi, shall also be exercisable by-

- (a) the Collector, within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident, in relation to the districts of—
- Raipur in the State of Chhattisgarh;
  - Ahemdabad, Gandhinagar and Kutch in the State of Gujarat;
  - Bhopal and Indore in the State of Madhya Pradesh;
  - Nagpur, Mumbai, Pune and Thane in the State of Maharashtra;
  - Jodhpur, Jaisalmer and Jaipur in the State of Rajasthan;
  - Lucknow in the State of Uttar Pradesh; and
  - West Delhi and South Delhi in the Union territory of Delhi; and

- (b) the Secretary of the Department of Home of the State or the Union territory, as the case may be, within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident, in relation to districts not covered under clause (a), in accordance with the provisions of the Citizenship Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules), subject to the following conditions, namely:-
- (A) the application for registration as citizen of India or grant of certificate of naturalisation as citizen of India under the said rules is made by the applicant online;
- (B) the verification of the application is done simultaneously by the Collector or the Secretary, as the case may be, at the district level and the State level and the application and the reports thereon shall be made accessible simultaneously to the Central Government on online portal;
- (C) the Collector or the Secretary, as the case may be, makes such inquiry as he considers necessary for ascertaining the suitability of the applicant and for that purpose forwards the application online to such agencies for verification and comments as may be required for completing such an inquiry and the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard shall be strictly complied with by the State or Union Territory and District concerned.
- (D) the comments of the agencies referred to in clause (C) are uploaded online by such agencies and accessible to the Collector or the Secretary, as the case may be, and the Central Government;
- (E) the Collector or the Secretary, as the case may be, on being satisfied with the suitability of the applicant, grants him/her the citizenship of India by registration or naturalisation and issue a certificate of registration or naturalisation, as the case may be, duly printed from online portal and signed by the Collector or the Secretary, as the case may be, in the Form as prescribed in the said rules; and
- (F) the Collector and the Secretary shall maintain an online/digital as well as physical register, in accordance with the said rules, containing the details of persons so registered or naturalised as a citizen of India and furnish a copy thereof to the Central Government within seven days of such registration or naturalization.

2. This Order shall come into force with effect from the 22<sup>nd</sup> December, 2018 and shall remain in force until further order.

[F. No. 26030/266/2014-IC-II (S.O.)]

ANIL MALIK, Jt. Secy.